विजेंदर जैन, **मुख्य न्यायमूर्ति** *और महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति* **के** *समक्ष*

सतीश गुप्ता और अन्य, — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — प्रतिवादी

सी.एम. 2008 की संख्या 5394
2007 की सीडब्ल्यूपी नंबर 10771

25 जुलाई, 2008

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — तथ्यों को छिपाना — उच्च न्यायालय ने आवेदन और निपटान के लिए **हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'एचएसआईडीसी')** ***को निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं की अपील — याचिकाकर्ताओं की अपील पहले ही उचित सुनवाई के बाद निपटाई जा चुकी है — उच्च न्यायालय से तथ्यों को रोकना — याचिकाकर्ता प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहे — याचिका खारिज, प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने वाला पूर्व आदेश वापस लिया गया।***

अभिनिर्धारित किया गया संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए -बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, निषेध के लिए -प्रिनिटेशन की याचिका, प्रवर्तन के लिए -परमादेश याचिका, प्रति-वारंट और प्रमाण पत्र की प्रकृति में याचिका सहित निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता अनिवार्य रूप से एक

न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, अदालत उन लोगों की सुनवाई करने से इनकार कर देगी, जो साफ हाथों से नहीं आते हैं। इसी तरह राहत, देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है और राहत देने से उस व्यक्ति को इनकार कर दिया जाएगा, जिसने न्याय के प्रशासन की प्रणाली को प्रदूषित करने की कोशिश की थी

(पैरा 10)

वीरेंद्र जैन, मुख्य न्यायाधीश।

(1) यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन है जिसे प्रतिवादी नं. 2 हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'एचएसआईडीसी') को वापस बुलाने के लिए हमारा ऑर्डर दिनांक 20th जुलाई, 2007,- सीडब्ल्यूपी. नं. 2007 के 10771 का निपटान किया गया था।

(2) रिट याचिका का निपटान करते समय, **हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** (एचएसआईडीसी) को उपरोक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर आवेदन के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं (गैर-आवेदकों) की अपील का निपटान करने का निर्देश जारी किया गया था ।

(3) इस आदेश को वापस लेने का मुख्य कारण यह बताया गया है कि जिस तारीख को यह आदेश पारित किया गया था, उस तारीख को याचिकाकर्ताओं की अपील, जैसा कि उसमें

निर्दिष्ट किया गया था, 24 जनवरी, 2007 को उचित सुनवाई के बाद पहले ही निपटाई जा चुकी थी-13 फरवरी, 2007 के आदेश द्वारा, जो उन्हें विधिवत सूचित किया गया था-20 फरवरी, 2007 के पत्र द्वारा।

(4) इस आवेदन के साथ, याचिकाकर्ताओं द्वारा हरियाणा सरकार की अपीलीय समिति के अध्यक्ष को 14 फरवरी, 2007 को लिखे गए पत्र को अनुबंध आर2/1 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसमें 20 फरवरी, 2007 को 13 फरवरी, 2007 के आदेश की प्राप्ति को स्वीकार किया गया था।

(5) उपरोक्त पत्र का प्रासंगिक अर्क दिनांक 14 फरवरी, 2007, को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: —

"मैं, सतीश गुप्ता, श्री बाबू लाल बंसल के साथ, अपीलीय समिति के समक्ष शाम को उपस्थित हुआ, 14 फरवरी, 2008, पत्र सं. HSIDC के संदरभ के। एस्टेट 2008/ 19567-68, दिनांक 7 फरवरी, 2008. पिछली बार, 24 जनवरी, 2007, मैं समिति के समक्ष अकेले उपस्थित हुआ मेरी अपील के संदर्भ में। मेरी सुनवाई के बाद, समिति 13 फरवरी, 2007 को एक आदेश पारित किया गया, जिसे प्राप्त हुआ *मुझे,* — *वीडियो* पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2007, मेरी अपील स्वीकार नहीं की गई और वही खारिज कर दी ।

(6) अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं/गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा 19 जुलाई, 2007 को रिट

याचिका दायर की गई थी, जिसका विधिवत समर्थन एक हलफनामे द्वारा किया गया था जिसमें एक अभिकथन किया गया था कि अपील अभी भी लंबित थी और सुनवाई और निपटान से संबंधित घटनाओं का पूरा क्रम न्यायालय से रोक दिया गया था, जिसके कारण 20 जुलाई, 2007 का आदेश पारित किया गया था।

(7) याचिकाकर्ताओं/गैर-आवेदकों के विद्वान वकील डॉ. सूर्य प्रकाश यह कहने के अलावा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि यह 'एक वास्तविक' गलती थी।

(8) हम याचिकाकर्ताओं/गैर-याचिकाकर्ताओं के रुख से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। एक व्यक्ति, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, उसे स्पष्ट हाथों के साथ आना पड़ता है।

(9) दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ताओं/गैर-याचिकाकर्ताओं की वास्तविकताओं पर ऊपर बताए गए तथ्यों से गंभीर रूप से संदेह पैदा हो गया है।

(10) संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, आदेश, निषेध, प्रति-वारंट और प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता अनिवार्य रूप से एक न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, न्यायालय उन लोगों की सुनवाई को अस्वीकार कर देगा, जो साफ हाथों से नहीं आते हैं। इसी तरह, छुट्टी देने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है और राहत देने से उस व्यक्ति को इनकार कर दिया जाएगा, जिसने न्याय के प्रशासन की प्रणाली को प्रदूषित करने की कोशिश की थी

(11) **हरि नारायण बनाम बद्री दास**[1] मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई आपत्ति को बरकरार रखा कि अपीलार्थी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का दोषी था और निम्नलिखित टिप्पणियां करके राहत को रद्द कर दिया:-

> "यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कला के तहत किए गए विशेष अवकाश के लिए आवेदनों में भौतिक बयान देने और आधार निर्धारित करने में। संविधान की धारा 136 के अनुसार, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा कोई बयान न दिया जाए जो गलत, असत्य या भ्रामक हो।"

विशेष अनुमति के लिए आवेदनों से निपटने में, न्यायालय स्वाभाविक रूप से याचिकाओं में निहित तथ्य और तथ्य के आधार के बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लेता है और असत्य और भ्रामक बयान देकर न्यायालय के विश्वास के साथ विश्वासघात करना अनुचित होगा। इस प्रकार, यदि अपील की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विशेष अनुमति के लिए अपने आवेदन में अपीलार्थी द्वारा दिए गए भौतिक कथन गलत और भ्रामक हैं और प्रत्यर्थी यह तर्क देने का हकदार है कि अपीलार्थी ने विशेष अनुमति के लिए याचिका में निहित तथ्यों के गलत निरूपण के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त की होगी, तो उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि ऐसे मामले में अपीलार्थी को दी गई विशेष अनुमति को निरस्त किया जाना चाहिए।

(12) **वेलकम होटल और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[2] में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पक्ष जिसने पक्ष में आदेश पारित करने में न्यायालय को गुमराह किया है, वह न्यायालय द्वारा सुने जाने का हकदार नहीं है।

---

[1] AIR 1963 S.C. 1558.

[2] AIR 1983 S.C. 1015.

(13) **नारायणस्वामी रेड्डी और अन्य बनाम**[3] कर्नाटक के राज्यपाल और एक अन्य (3) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने इस तथ्य को छिपाया था कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए में निर्दिष्ट समय के भीतर एक रिट याचिका में पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण अधिनिर्णय नहीं दिया गया था। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहाः –

"दिलचस्प बात यह है कि विशेष अनुमति याचिकाओं में किसी भी स्थगन आदेश का कोई संदर्भ नहीं है और हमें इन आदेशों के बारे में तब पता चला जब प्रतिवादी नोटिस के जवाब में पेश हुए और अपना जवाबी हलफनामा दायर किया । हमारा विचार है कि उक्त अंतरिम आदेशों का उठाए गए प्रश्न पर सीधा असर पड़ता है और इसका खुलासा न करना निश्चित रूप से भौतिक तथ्यों को दबाने के बराबर है। केवल इसी आधार पर, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं। यह विधि में अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद. 136 के अधीन राहत विवेकाधीन है और ऐसी राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता को तथ्यों के स्पष्ट और पूर्ण प्रकटीकरण के साथ आना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है और भौतिक तथ्यों को दबाता है, तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है। हम तदनुसार विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हैं।

---

[3] AIR 1991 S.C. 1726.

(14) में **एस.पी. चेंगालवारया नायडू (मृत) एल.आर** *बनाम* **जगन्नाथ (मृत) एल.आर. और अन्य द्वारा,**[4] उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां न्यायालय में धोखाधड़ी करके प्रारंभिक डिक्री प्राप्त की गई थी क्योंकि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को दूसरे पक्ष से लाभ प्राप्त करने के लिए रोक दिया गया था, ऐसे पक्षकार मुकदमे के किसी भी स्तर पर निष्कासित किए जाने के पात्र ।

(15) में **नंद लाल और अन्य** *बनाम* **जम्मू राज्य और कश्मीर और एक और अन्य द्वारा**[5], जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई पक्ष सभी तथ्यों का सही और स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं करता है, तो वह मामले के गुण-दोष पर सुनवाई का हकदार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत किया गया है नीचे:

> “-"जहाँ अनुच्छेद 226 के अधीन याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के समर्थन में प्रासंगिक तथ्य याचिका या हलफनामे में नहीं कहा है, यह अपने आप में रिट याचिका के गुण-दोष में गए बिना उसे पूरी तरह से खारिज करने के लिए पर्याप्त है। और भले ही याचिकाकर्ताओं के पास गुण-दोष के आधार पर एक अच्छा मामला हो, न्यायालय गुण-दोष में जाने और उनकी याचिका को खारिज करने से इनकार करने का हकदार होगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा है जिससे न्यायालय को गुमराह किया जा सके।”

(16) इस न्यायालय ने भी लगातार एक गंभीर स्थिति ली है *दृश्य* का पार्टियों के आकस्मिक आचरण और एक में राहत से इनकार कर दिया है बड़ी संख्या में मामले ।

---

[4] AIR 1991 S.C. 1726

[5] AIR 1960 Jammu & Kashmir 19

(17) में **भूपिंदरपाल कौर** *बनाम* **वित्तीय आयुक्त *(राजस्व)*, पंजाब**[6]**,** एक सीखा एकल न्यायाधीश ने आयोजित किया

[6] 1968 P.L.R. 169.

यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समर्थन में शपथ पत्र रिट के अनुदान के लिए आवेदन स्पष्ट नहीं था और पूरी तरह से राज्य नहीं था तथ्यों लेकिन या तो भौतिक तथ्यों को दबा दिया, जिसके लिए न्यायालय को चाहिए अपनी सुरक्षा और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, आगे बढ़ने से इनकार करें योग्यता की परीक्षा के साथ आगे और जहां ऐसा है आचरण जो आदेश देने में न्यायालय को धोखा देने के लिए गणना की जाती है नियम nisi की, याचिका को उस छोटी जमीन पर खारिज कर दिया जाना चाहिए ।

(18) **चिरनजी लाइ और अन्य** *बनाम* **वित्तीय आयुक्त** में**, हरियाणा और अन्य**[7], पूर्ण बेंच ने टिप्पणियों को मंजूरी दी भूपिंदरपाल कौर के मामले (सुप्रा) में बनाया गया और वहां आयोजित किया गया रहा है *माला फाइड* और भौतिक तथ्यों की गणना की गई दमन अगर, अगर खुलासा किया गया है तो याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया जाएगा रिट क्षेत्राधिकार के तहत या किसी भी मामले में असाधारण उपाय अंतरिम और अंतिम दोनों पर गुण को प्रभावित करेगा राहत का दावा किया गया, रिट याचिका का मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए ।

(19) **हरभजन कौर** *बनाम* **पंजाब और अन्य राज्य** में [8]**,** एक डिवीजन बेंच के तहत आयोजित: —

> ःरिट याचिकाकर्ताओं ने अदालत तक पहुंचने की कोशिश की है। उन्होंने न्यायालय के ध्यान में सही तथ्य नहीं लाए और हमसे आदेश पर भौतिक तथ्यों को छिपाकर और रिट याचिका में गंभीर रूप से प्रभावित पक्ष को शामिल किए बिना प्राप्त किया। वे 1986 से पंजाब वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जैसा कि

[7] 1978 P.L.R. 582.

[8] 1994 P.L.J 287.

याचिका सं. 1986 का 363. **(शाम सिंह और एक अन्य** *बनाम* **पंजाब वक्फ बोर्ड)** उन्होंने यह खुलासा नहीं किया उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि जमीन के हस्तांतरण के लिए उनके आवेदन तहसीलदार (बिक्री) द्वारा खारिज कर दिए गए थे और अपील पर आदेशों की बिक्री आयुक्त द्वारा पुष्टि की गई थी और बिक्री आयुक्त के आदेशों के खिलाफ अपील मुख्य बिक्री आयुक्त के समक्ष लंबित थी, कि पंजाब वक्फ बोर्ड उनके दावे को चुनौती दे रहा था और उन कार्यवाही में यह माना गया था कि पंजाब वक्फ बोर्ड विवादित भूमि का मालिक था और न्यायिक कार्यवाही में श्रीमती. कुलदीप कौर और उनके पति ने स्वीकार किया था कि विवादित जमीन का मालिक पंजाब वक्फ बोर्ड है।."

(20) **सीडब्ल्यूपी** में. 15448 की संख्या **1993-जय भगवन जैन** *बनाम* **हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकुला जिला अंबाला),**

21 सितंबर, 1994 को इस न्यायालय इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने वादियों के बीच न्याय के मार्ग को प्रदूषित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अफसोस जताया और कहा कि: —

> "सत्य और अहिंसा दो मूल मूल्य हैं जीवन के दो बुनियादी मूल्य हैं, जिन्हें महावीर और महात्मा गांधी की इस भूमि में सदियों से पोषित किया गया है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग जीवन के इन बुनियादी सिद्धांतों को सीखने के लिए यहां आते हैं। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद के युग और विशेष रूप से पिछले दो दशकों में जीवन के इन दो बुनियादी मूल्यों में तेज गिरावट देखी गई है। भौतिकवाद ने पुराने लोकाचार को भारी कर दिया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी विशाल है कि लोगों में 'सत्य' के लिए कोई सम्मान नहीं है। अदालतों में कार्यवाही, जिसे एक समय में पवित्र माना जाता था और लोग अदालत में सच बताना अपना कर्तव्य मानते थे, अब पक्षकारों द्वारा न्याय के उद्देश्यों को प्रदूषित करने के प्रयासों से दूषित हो गए ."

(21) इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था **पवन कुमार** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य**[9]**; एम / एस काका राम पारस राम और ओआरएस.** *बनाम* **पंजाब राज्य और अन्य,**[10]**;** सीडब्ल्यूपीनहीं. 11686 1996 का ; **श्री कांत और ओआरएस.** *बनाम* **पंजाब राज्य और अन्य,** फैसला किया 20 जनवरी, 1997 को; सीडब्ल्यूपी1998-एम / एस की संख्या 4381 **अरिहंत सुपर चावल की भूमि और ओआरएस.** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य,** पर फैसला किया 6 अगस्त, 1998; सीडब्ल्यूपी18304 की संख्या **1998-Smt. कृष्ण गुप्ता** *बनाम* **हरियाणा राज्य और ओआरएस.,** 1 दिसंबर, 1998 को निर्णय लिया गया और सीडब्ल्यूपी2585 की संख्या **1999-सांता सिंह** *बनाम* **भारत संघ और अन्य,** 24 फरवरी, 1999 को निर्णय लिया गया;

---

[9] 1994(5) S.L.R. 73.
[10] 1996(1) P.L.R. 691

सीडब्ल्यूपी1999 की संख्या 11538- **मीनू सेठ** *बनाम* **पंजाब राज्य और अन्य,** फैसला किया मार्च, 2000, सीडब्ल्यूपी3520 की संख्या **2000-राजिंदर परशाद और अन्य** *बनाम* **भारत संघ और अन्य,** 31 मई, 2000 को निर्णय लिया गया और सीडब्ल्यूपीकी संख्या 8239 **2004-परवीन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य और दूसरे,** 3 जुलाई, 2004 को निर्णय लिया गया।

(22) इस विषय पर कुछ अंग्रेजी निर्णयों का भी संदर्भ दिया जा सकता है। रेक्स बनाम केंसिंगटन[11]कोजेंस हार्डी एमआर मे एक पार्टी के आचरण पर निम्नलिखित टिप्पणियों किया, निम्नलिखित शब्दों में एकतरफा आवेदनः -

> "एक एकतरफा आवेदन पर 'उबेर्रिमा फिडेस' की आवश्यकता होती है, और जब तक कि यह स्थापित नहीं किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ है"

---

[11]) 1917 (I)K.B. 486

न्यायालय को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए, बल्कि केवल यह कहना चाहिए कि आपने जो किया है उसके कारण हम आपके आवेदन को नहीं सुनेंगे।"

लॉर्ड स्क्रूटन एल.जे. ने कहा: —

"इसमें कई वर्षों से न्यायालय का नियम है और जिसे बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब कोई आवेदक एकतरफा बयान पर राहत प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आता है तो उसे सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण और निष्पक्ष प्रकटीकरण करना चाहिए, न कि कानून का।आवेदक को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए और जिस दंड के द्वारा न्यायालय उस दायित्व को लागू करता है, वह यह है कि यदि उसे पता चलता है कि तथ्यों को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से कहा गया है, तो न्यायालय किसी भी कार्रवाई को रद्द कर देगा जो उसने अपूर्ण कथन के विश्वास पर की है।"

(23) **आर.वी. चर्चवर्ड ओएफ ऑल सेंट्स विगन**[12]**, लॉर्ड** हटेरलय मनाया: —

"एक विशेषाधिकार रिट पर विवेकाधिकार के कई मामले उत्पन्न हो सकते हैं जो न्यायाधीशों को विलंब या संभवतः पक्षों के आचरण से जुड़े मामलों के अनुदान को रोकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ”

(24) **रेक्स बनाम गारलैंड**[13]**,** यह आयोजित किया गया था:-

"जहां कोई प्रक्रिया एकतरफा न्यायसंगत है, वहां न्यायालय आवेदक के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से

[12] (12) (1876) 1A.C. 611.

[13] (1870) 39 L.R. Q.B. 26.

इनकार कर देगा, जहां आवेदन वास्तविक रूप से वांछित नहीं पाया गया है,"

(25) नतीजतन, नतीजतन, हम इस आवेदन को स्वीकार करते हैं, 20 जुलाई, 2007 के अपने आदेश को याद करते हैं और तथ्यों को छिपाने के आधार पर रिट याचिका को खारिज करते हैं ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
पानीपत, हरियाणा